अनुसूचित जाति समुदाय के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आयोग न केवल अनुसूचित जाति को न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा बल्कि समुदाय के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए भी सक्रिय रहेगा। उन्होंने कहा कि आयोग अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और सलाह देने और उनके खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए काम करेगा।

-राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष, किशोर मकवाना

मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेश विकसित अग्नि-5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण संपन्न हुआ और इसके लिए उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैज्ञानिकों को बधाई दी। मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर गर्व है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेश विकसित अग्नि -5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण।

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

बराक घाटी में किरण शेख समुदाय लंबे समय से विकास परिषद की मांग कर रहा था। अन्य समुदायों के लिए ऐसी ही विकास परिषदों की तर्ज पर कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर मणिपुरी भाषा में शिक्षा के लिए मेइती लिपि के इस्तेमाल पर भी सहमति दे दी है। कैबिनेट ने जोरहाट शहर में जलापूर्ति योजना, करीमगंज मेडिकल कॉलेज के निर्माण, रंग घर सौंदर्यीकरण परियोजना और अमीनगांव खेल परिसर सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि की प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी।

-असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ

सूची घोषित करती कांग्रेस और सेंध लगाती भाजपा

मैं स्वामी शंकराचार्य स्वरुपानंद का दीक्षित शिष्य हूं मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भेजा कि जाओ शंकराचार्य जी से पूछ कर आओ कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में शिलान्यास हो और मंदिर बने। सितम्बर 1999 में राजीव जी ने जवाब दिया कि तदानुसार काम हो फिर हम तत्कालीन गृहमंत्री बूटासिंह के साथ गये और वहां शिलान्यास किया। वहां अशोक सिंघल जी भी थे, फिर अब निमंत्रण पत्र अस्वीकार करने की आवश्यकता कहां से पड़ गयी। राम मंदिर का ताला खुलना, शिलान्यास होना किसके कार्यकाल में हुआ यह बोला जा सकता था।

बिग न्यूज

-अरुण पटेल-
(स्वतंत्र लेखक)

लोकसभा चुनाव में 400 पार की जुगत करने के लिए जहां भाजपा अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का पलायन भी भाजपा की ओर उसी तेजी से हो रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां-जहां से गुजर रही है वहां भी कोई न कोई बड़ा कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो रहा है। मध्यप्रदेश में भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का अभियान छेड़े हुए हैं ताकि कांग्रेस को मैदान के साथ ही मनोवैज्ञानिक शिकस्त भी दें तथा कांग्रेस नेताओं व कार्यकताओं में जो हार की हताशा से उबरने की कोशिश कर रहे हैं फिर नैराश्य की वादियों में खो जायें। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में कोई दलबदल अभी तक नहीं हुआ है लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते इसकी संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि भाजपा ऐन केन प्रकारेण कांग्रेस को राजनीतिक फलक पर अप्रासंगिक करने की मुहिम छेड़े हुए है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के उन कार्यकताओं व नेताओं में उम्मीद भी जाग रही है कि अब उन्हें अपनी पार्टी में कुछ मौका मिल जाये जिन्हें नेताओं की गणेश परिक्रमा न करने के कारण कोई मौका नहीं मिल पाता था। कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल और अभी तक सबको चुनाव लड़ाने वाले और राज्यसभा के माध्यम से सांसदी का लाभ लेने वाले के. सी.वेणुगोपाल को भी अब लोकसभा चुनाव लडना होगा। इस प्रकार कुछ और कांग्रेस नेताओं की अग्नि परीक्षा अब चुनाव में हो सकती है जो अभी तक चुनाव से बचते रहते थे। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के एक बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने आज अपने अधिकांश समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश कर लिया है। जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं उनमें इंदौर के पूर्व कांग्रेसी विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और अब कांग्रेस नेता बने अर्जुन पलिया, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष रहे आलोक चंसोरिया, भोपाल नगर पालिक निगम के सभापति रहे कैलाश मिश्रा तथा योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश ढिमोले, जसपाल सिंह अरोरा शामिल हैं। इस अवसर पर सुरेश पचौरी ने कहा कि भगवान श्रीराम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा था जिसके निमंत्रण पत्र को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर जब ठुकरा दिया गया तब मुझे आघात पहुंचा, मैं अयोध्या में राम मंदिर का पक्षधर आरंभ से रहा हूं, निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं स्वामी शंकराचार्य स्वरुपानंद का दीक्षित शिष्य हूं मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भेजा कि जाओ शंकराचार्य जी से पूछ कर आओ कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में शिलान्यास हो और मंदिर बने। सितम्बर 1999 में राजीव जी ने जवाब दिया कि तदानुसार काम हो फिर हम तत्कालीन गृहमंत्री बूटासिंह के साथ गये और वहां शिलान्यास किया। वहां अशोक सिंघल जी भी थे, फिर अब निमंत्रण पत्र अस्वीकार करने की आवश्यकता कहां से पड़ गयी। राम मंदिर का ताला खुलना, शिलान्यास होना किसके कार्यकाल में हुआ यह बोला जा सकता था। भाजपा में उपरोक्त नेताओ को शामिल करने के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन वास्तव में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। वैसे तो सबको आहट थी कि जहां-जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस के काम करने के तरीके का असर आता है। अच्छे स्थापित स्वच्छता के साथ राजनीति करने वाले, मन की भावनाओं के आधार पर काम करने वाले नेता हर दल के अंदर होते हैं लेकिन साफ-सुथरी राजनीति करने वालों को काम करने की अनुकूलता देना, मौका देना, यह नेतृत्व पर निर्भर करता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे स्वच्छता व साफ सोच के साथ राजनीति करने वाले नेता जो देश के विकास के लिए राजनीति करते हैं ऐसे लोगों को निराश करता है, ऐसे में कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कांग्रेस के लिए काम नहीं करना चाहेगा। मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी दो-तीन यात्राएं और निकालें क्योंकि अभी जहां-जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां-वहां कांग्रेस साफ होती जा रही है। डॉ. यादव ने कहा कि महात्मा गांधी की भावना को सही साबित करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि आज की घटना मध्यप्रदेश की राजनीति की असाधारण घटना है। सुरेश पचौरी जी के संस्कारों का मैं आरंभ से ही कायल था। वह दो-दो पीएम के साथ रहे लेकिन उनके दामन में एक भी दाग नहीं लगा, जिन पदों पर उन्होंने काम किया वहां उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वह एक दिशाहीन नेता के नेतृत्व में काम कर रही है। यह अदभुत समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, पचौरीजी मेरे सीनियर रहे हैं, मैं उनका जूनियर रहा हूं। अब साथ काम करने का मौका मिलेगा। राम वन पथ गमन का विकासडॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही राम वन पथ गमन के विकास में गति आ गयी है। पहले आरंभ में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जोरशोर से राम पथ गमन का काम आरंभ हुआ था, लेकिन फिर उसकी गति कुछ धीमी हो गई। बाद में एक प्रकार से वहां नाममात्र के काम ही हुए। लेकिन डेढ़ दशक बाद जब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी तब उन्होंने फिर से इसकी सुध ली और काम में तेजी आई। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व संभालने के साथ ही राम वन पथ गमन के जो काम हो रहे थे उनमें तेजी आ गयी और इसके विकास की जिम्मेदारी सात विभागों को दे दी गयी है। लोकसभा चुनावों के बाद ये विभाग पूरे विकास कार्यों का ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे।

अनास्था की सदी में खाटू आस्था का मेला

-निमिषा सिंह-

लोकतंत्र

वीर प्रसूता राजस्थान की माटी ने यूं तो अपने आंचल में उत्कृष्ट शोर्य परंपरा से जुड़ी अनेको गौरव गाथाओं को समेटा हुआ है किंतु राजस्थान का जिक्र हो और आस्था के प्रमुख केन्द्र खाटू की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विशेषकर मुझ जैसे लाखों भक्तों के लिए जिनका मानना है कि खाटू में विराजमान बाबा श्याम से अगर एक बार कुछ मांगा तो वो लाखों करोड़ों बार देते है और देते ही रहते हैं। यही कारण है कि हम भक्त उन्हें लखदातार के नाम से भी पुकारते है। राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। यहाँ विराजित हैं भगवान श्रीकृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्यामजी। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यहां देवता के केवल सिर की पूजा होती है। यहां की मूर्ति का कोई धड़ नहीं है। धड़विहीन मूर्ति बाबा श्याम की है जिनकी कहानी महाभारत और स्कंद पुराण से संबंधित है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने-कोने में मौजूद है। हर वर्ष फाल्गुन के महीने में यहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। फाल्गुन के महीने अर्थात मार्च में बाबा खाटू श्याम जी का लक्खी मेला लगता है साथ ही बाबा का जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 2024 में बाबा श्याम का यह मेला 11 मार्च से प्रारंभ होगा और 21 मार्च तक इसका समापन होगा। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये पांडुपुत्र भीम के पोते थे। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियों और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलियुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दे डाला था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर-उधर घूम रहे थे तब भीम का सामना हिडिम्बा से हुआ। हिडिम्बा ने भीम से एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। इसी घटोत्कच और अहिलावती (मोरवी) के सबसे बड़े पुत्र हुए बर्बरीक। उनके अन्य भाई अंजनपर्व और मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। इन सबों को वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। बर्बरीक को उनकी माता मोरवी ने यह सीख दी कि सदा ही पराजित पक्ष की तरफ से युद्ध करना और वे इसी सिद्धांत पर आजीवन अड़े रहे। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ हैं?तब उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। चूंकि श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे लिहाजा उन्हें आसंका थी कि बर्बरीक कहीं पांडवों के लिए खतरा ना बन जाए। ऐसे में कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे उनका शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश तो दे दिया लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध स्थान के निकट एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है तब बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से आप सबों को जीत हासिल हुई है। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलियुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरूआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। इस चमत्कारिक जगह पर खुदाई की गई को तो यहां खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा शुरू हो गई कि इस सिर का किया जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया और उसी स्थान पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया। मंदिर निर्माण ले पश्चात खाटूश्याम की मूर्ति वहां स्थापित की गई। 1027 में रूप सिंह द्वारा बनवाए गए मंदिर का पुनर्निर्माण खाटू श्याम के भक्त दीवान अभय सिंह ने 1720 ई. में किया। इतिहासकार पंडित झाबरमल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राण न्योछावर किया था। इस मंदिर में बाबा श्याम के मस्तक स्वरूप की पूजा होती है जबकि निकट ही स्थित रींगस में उनके धड़ स्वरूप की पूजा की जाती है। पिछले साल जून के महीने में मेरा पहली बार खाटू जाना हुआ। ऐसा लगा मानो बाबा श्याम का बुलावा आया है। मैं दिल्ली से वाया रोड खाटू श्याम गई थी जिसमे 5 से 6 घंटे का समय लग गया था। खाटू श्याम का मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद है।

किसानों के लिए सरकार की अहम पहल

नई खाद्यान्न भंडार योजना वस्तुत : देश में भंडारण के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नई विशाल भंडारण क्षमता के बाद किसान अपनी उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले संस्थागत ऋण प्राप्त करने और बाजार मूल्य लाभकारी होने पर अपने खाद्यान्न को बेचने में सक्षम होंगे। नई खाद्यान्न भंडार योजना का मकसद देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, भंडारण क्षमता में कमी के कारण किसानों को फसल पैदावार के मौसम में कम मूल्य पर की जाने वाली बिक्री से होने वाले नुकसान से बचाना भी है। इस समय देश का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 3200 लाख टन से भी अधिक है, जबकि भंडारण क्षमता कुल उत्पादन का केवल 47 प्रतिशत ही है।

रणनीति

-डा. जयंतीलाल भंडारी-
(स्वतंत्र लेखक)

देश में किसानों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के द्वारा किसानों के हित में उठाई गई दो महत्वपूर्ण पहलें दुनियाभर में रेखांकित हो रही हैं। एक, हाल ही में भारत के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबूधाबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्नों के सार्वजनिक भंडारण एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी पहल की गई, जिसके कारण इस सम्मेलन में इन मुद्दों पर कई विकसित देश भारत के किसानों के हितों के प्रतिकूल कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा पाए। ऐसे में अब भी भारत अपने किसानों के उपयुक्त लाभ के लिए नीतियां बनाने में सक्षम है। दो, 24 फरवरी को सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के लिए प्रायोगिक परियोजना लांच की है। यह प्रायोगिक परियोजना 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को लक्षित कर रही है, जिनके माध्यम से पैक्स की किसानों के हित में बहुआयामी भूमिका होगी। गौरतलब है कि कृषि पर अबूधाबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने जी-33 देशों के समूह, अफ्रीकी देशों और प्रशांत देशों के समूह की आवाज के साथ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग (पीएचएस) के स्थायी समाधान को अंतिम रूप देने के लिए मजबूती से पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि अब डब्ल्यूटीओ को केवल निर्यातक देशों के व्यापारिक हितों तक ही अपना ध्यान सीमित नहीं रखना चाहिए, असली चिंता दुनिया के करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका की होनी चाहिए। वस्तुतः खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक भंडारण के लिए भारत सरकार गेहूं और चावल मोटे अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की पहले से तय कीमत पर खरीदती है और फिर उन्हें गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सस्ते दाम या मुफ्त में वितरित करती है। यह खाद्य सुरक्षा भूख से त्रस्त लाखों लोगों को भूख से बचाने का सरकार का नीतिगत तरीका है। यह भारत के द्वारा वर्ष 2030 तक देश में भूख व गरीबी मिटाने के लक्ष्य से जुड़ा मुद्दा भी है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक 1986-88 के मूल्यों को आधार मानते हुए उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। भारत इसमें बदलाव चाहता है ताकि किसानों को अधिक सब्सिडी देने पर वैश्विक मंच पर उसका विरोध नहीं हो सके। अमरीका सहित कई विकसित राष्ट्र खाद्यान्न के लिए भारत में दिए जा रहे एमएसपी कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि इस पर दी जा रही सब्सिडी डब्ल्यूटीओ व्यापार नियमों के तहत स्वीकृत सीमा से करीब तिगुनी हो गई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2013 में बाली में हुए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सार्वजनिक भंडारण और खाद्य सुरक्षा को लेकर एक पीस क्लॉज पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके तहत अन्न भंडारण कार्यक्रम का स्थायी हल नहीं निकलने तक किसी भी देश के द्वारा अनाज की खरीददारी और उसे कम दाम पर लोगों को देने का विरोध नहीं किया जाएगा। भारत को आशंका है कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर रोक लगाई जाएगी तो इससे देश के करोड़ों लोगों की भूख, करोड़ों किसानों की आजीविका और भारतीय कृषि के भविष्य पर असर पड़ सकता है। इसी कारण भारत खाद्य सब्सिडी की सीमा तय करने का फॉमूर्ला बदलने की मांग कर रहा है। निश्चित रूप से इस समय जब भारत 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, देश में अभी भी 15 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और भारत को कुपोषण की समस्या से ग्रसित देश के रूप में रेखांकित किया जा रहा है, तब भारत में खाद्य सुरक्षा, अधिक खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यन्न भंडारण की जरूरत बनी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार के सराहनीय प्रयास दिखाई भी दे रहे हैं। जहां सरकार डब्ल्यूटीओ सहित अन्य वैश्विक मंचों पर किसानों को अधिक समर्थन को न्यायसंगत बताती है, वहीं हाल ही में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लांच की गई दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत अगले पांच साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 700 लाख टन अनाज की भंडारण क्षमता के हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि अब कम्प्यूटरीकृत पैक्स को गोदाम तैयार करने, कस्टर हायरिंग सेंटर बनाने, उचित मूल्य की दुकानों की प्रक्रिया में तथा प्रसंस्करण इकाइयां तैयार करने जैसी बहुआयामी भूमिका में शामिल किया गया है।

देश में चुनावों से पहले विकास की बरसात....

-राकेश अचल-

चुनाव

लोकसभा चुनाव से पहले देश में विकास की ऐसी बरसात हो रही है कि पिछड़ापन लगता है कहीं बचेगा ही नहीं। हम कल की ही बात करें तो एक ही दिन में सरकार ने 6 नए हवाई अड्डे, छह नए टर्मिनल का लोकार्पण करने के साथ ही हजारों करोड़ रुपए की नयी योजनाओं की आधारशिलाएं रख दीं। देश में ये विकास राजनीति के पश्चिमी विक्षोभ का नतीजा है। न चुनाव होते और न देश में विकास की झड़ी लगती। लगता है कि सरकार विकास की मेघमाला को चुनावों के लिए ही रोककर रखती है। इस हवा-हवाई विकास की हकीकत क्या है ये समझना जरूरी है।

चुनावों से पहले देश में विकास की बरसात हमेशा से होती आई है किन्तु भाजपा की सिंगल और डबल इंजन की सरकारों ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए 370 और एनडीए गठबंधन के लिए 400 सीटें जीतने के आसमानी लक्ष्य को पाने के लिए विकास की बरसातों के सभी पुराने कीर्तिमान भंग कर दिए हैं। मौजूदा सरकार को कीर्तिमान भंग करने में महारत हासिल है। सरजू तट पर दीपक जलाने से लेकर, सरकारें खरीदने, गिराने और विकास की बरसातें करने तक के सभी पुराने कीर्तिमान हमारी इसी लोकप्रिय सरकार ने भंग किये हैं। कांग्रेस की अव्वल तो सरकारें कम हैं और जो भी हैं वे भी नए कीर्तिमान गढ़ने में भाजपा से कोसों पीछे हैं।

देश की जनता को हैरानी होती है की 74 साल के प्रधानमंत्री में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है जो वे उत्तर -पूर्व से लेकर पूरे देश में चुनावी दौरे ऐसे कर रहे हैं जैसे की कोई तूफान खड़ा करना कहते हों। प्रधानमंत्री ने 10 मार्च को ही 15 हवाई इंफ्रा स्ट्रक्चर का लोकार्पण किया। इनमें छह नए हवाई अड्डे शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी भले ही मणिपुर नहीं गए हों लेकिन वे उन सभी हिस्सों में गए जहाँ से सीटें मिल सकती है। वे बिहार गए, बंगाल गए, यूपी तो जाते ही रहते हैं। एमपी गए, महाराष्ट्र गए और जहाँ नहीं जा पाए वहां उन्होंने अपनी आभासी उपस्थिति (वर्चुअल) से लोगों को नवाजा। अतीत में ये क्षमता सुर और असुर दोनों पक्षों के पास थी। अब कलिकाल में ये मायावी शक्ति केवल सत्ता पक्ष के पास बची है।

दो-दो इंजन लगाकर सरकारें चलाने वाली भाजपा ने जान और मान लिया है कि जुमलेबाजी में विकास का छोंक लगाए बिना बात बनने वाली नहीं है। देश को आप चाहे हिन्दू राष्ट्र बनाइये, चाहे अहिन्दू राष्ट्र बिना विकास के बात बनने वाली नहीं है। किसी भी देश में विकास पहली जरूरत होती है। जहाँ विकास को तरजीह नहीं दी जाती वहां बारूद ही बारूद बिछी दिखाई देती है। आसपास नजरें उठाकर देख लीजिये, हकीकत समझ में आ जाएगी। राष्ट्र को राष्ट्र बनाये रखने के लिए सबसे पहले खुद को उदार बनाना जरूरी है। आप जुमलों से खुद को बिजूका बनाकर लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। और यदि कर रहे हैं तो ये आपका सौभाग्य है।

देश का विपक्ष और एक बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को खलनायक मानता है, किन्तु मै ऐसा नहीं मानता, क्योंकि खुद मोदी जी ऐसा नहीं मानते। वे भले ही देश की 31 फीसदी जनता द्वारा चुनी गयी भाजपा के नेता हैं लेकिन हैं तो देश के प्रधानमंत्री, इसलिए मै उन्हें खलनायक नहीं मान सकता भले ही वे खलनायकों की तरह व्यवहार करते नजर आते हों। खलनायक के भीतर भी तो एक नायक छिपा है। नायक, खलनायक और अधिनायक में जो गैर जरूरी शब्द हैं उन्हें यदि अलग कर दिया जाये तो शेष नायक ही बचता है। देश पर विकास की बरसात आखिर मोदी जी से, भाजपा से कोई अंतर्निहित नायक ही करा रहा है।

समस्या ये है कि हम या हमारी राजनीति कभी ये सवाल नहीं करती कि सरकारें विकास को एक सतत प्रक्रिया बनाये रखने के बजाय उसका इस्तेमाल एक चारे के रूप में क्यों करतीं है। सरकारों को विकास की याद न चुनावों के समय ही क्यों आती है? क्या वे चुनावों के लिए विकास को अवरुद्ध करने का अपराध नहीं करतीं? विकास को एक जरूरत के बजाय राजनीतिक हथियार क्यों बना दिया गया है? क्या इससे मुक्ति आवश्यक नहीं है, या सभी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर कोई दुरभि संधि कर ली है?